UN TO DRAFT FIRST-EVER TREATY ON OCEAN'S BIOLOGICAL DIVERSITY

Why in the News?

Recently, a delegation from India and other member countries of the United Nations, deliberated to draft the first-ever treaty on Ocean's Biological Diversity.

- The conference is being held at New York.

Key Points

About Ocean Diversity Pact:

- It is a one-of-its-kind agreement **to conserve marine biodiversity in the high seas**, namely the oceans that extend beyond countries' territorial waters.
- **International legally binding:** To draft an international legally binding instrument under the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).
- **Rights of the companies:** A key aspect of the agreement is deciding on the rights of companies that undertake exploration for biological resources in the high seas.
- Studies on sustainable utilisation of deep sea bio-resources will be the main focus.

Significance:

- Sustainable oceans and seas could contribute to poverty eradication, sustained economic growth, food security and creation of sustainable livelihoods.
- It would build resilience to the impacts of climate change.

Need:

- There was a "race" among international corporations for biological resources from the sea, making it critical to have an agreement on benefit-sharing.
- Not allow it to be monopolised by a few entities.

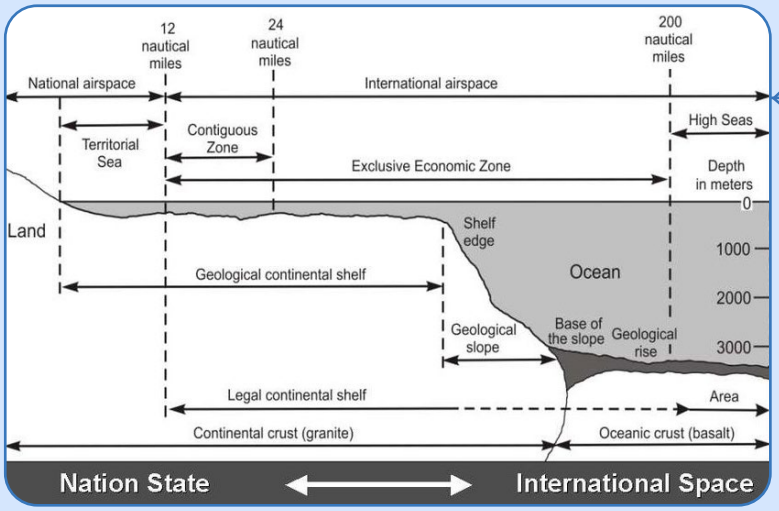

What are High Seas?

Image Source: ResearchGate

- Countries can protect or exploit waters under 200 nautical miles (370 kilometres) to their shorelines, but everything outside these 'exclusive economic zones' is considered international waters: the high seas.
- The high seas comprise nearly 45% of the Earth's surface.

Regulations of High Seas:

- UNCLOS regulates activities in international waters, including sea-bed mining and cable laying.
- It lays down rules for the use of the ocean and its resources, but does not specify how states should conserve and sustainably use high seas biodiversity.
- No overarching treaty exists to protect biodiversity or conserve vulnerable ecosystems in the oceans.

About The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS):

- The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), also called the Law of the Sea Convention is an international agreement adopted in 1982 that establishes a legal framework for all marine and maritime activities.

It has created three new institutions

1. **The International Tribunal for the Law of the Sea.**
2. **The International Seabed Authority.**
3. **The Commission on the Limits of the Continental Shelf.**

संयुक्त राष्ट्र महासागर की जैविक विविधता पर पहली बार संधि का मसौदा तैयार करेगा

खबरों में क्यों?

हाल ही में, भारत और संयुक्त राष्ट्र के अन्य सदस्य देशों के एक प्रतिनिधिमंडल ने महासागर की जैविक विविधता पर पहली संधि का मसौदा तैयार करने पर विचार-विमर्श किया।

- यह सम्मेलन न्यूयॉर्क में हो रहा है।

प्रमुख बिंदु

महासागरीय विविधता संधि के बारे में:

- यह उच्च समुद्रों में समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के लिए अपनी तरह का एक अनूठा समझौता है, अर्थात् महासागर जो देशों के क्षेत्रीय जल से परे हैं।
- **अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी:** समुद्र के कानून पर 1982 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) के तहत एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन का मसौदा तैयार करना।
- **कंपनियों के अधिकार:** समझौते का एक प्रमुख पहलू उन कंपनियों के अधिकारों पर निर्णय लेना है जो उच्च समुद्र में जैव संसाधनों की खोज करती हैं।
- गहरे समुद्र में जैव संसाधनों के सतत उपयोग पर अध्ययन मुख्य फोकस होगा।

महत्व:

- संधारणीय महासागर और समुद्र, गरीबी उन्मूलन, सतत आर्थिक विकास, खाद्य सुरक्षा और स्थायी आजीविका के सृजन में योगदान कर सकते हैं।
- यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति लचीलेपन का निर्माण करेगा।

आवश्यकता:

- समुद्र से जैविक संसाधनों के लिए अंतरराष्ट्रीय निगमों के बीच एक "दौड़" थी, जिससे लाभ-साझाकरण पर एक समझौता करना महत्वपूर्ण हो गया।
- इस पर कुछ संस्थाओं द्वारा एकाधिकार करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

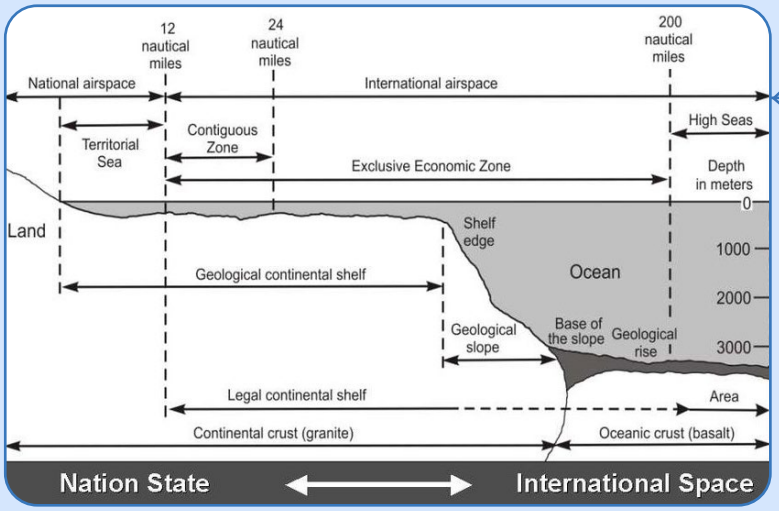

उच्च समुद्र क्या हैं?

छवि स्त्रोत: रिसर्चगेट

- देश अपनी तटरेखाओं तक 200 समुद्री मील (370 किलोमीटर) से कम पानी की रक्षा या दोहन कर सकते हैं, लेकिन इन 'अनन्य आर्थिक क्षेत्रों' के बाहर सब कुछ अंतरराष्ट्रीय जल माना जाता है: उच्च समुद्र।
- उच्च समुद्र में पृथ्वी की सतह का लगभग 45% हिस्सा है।

उच्च समुद्र के नियम:

- UNCLOS समुद्र तल खनन और केबल बिछाने सहित अंतरराष्ट्रीय जल में गतिविधियों को नियंत्रित करता है।
- यह समुद्र और उसके संसाधनों के उपयोग के लिए नियम निर्धारित करता है, लेकिन यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि राज्यों को उच्च समुद्र जैव विविधता का संरक्षण और स्थायी रूप से कैसे उपयोग करना चाहिए।
- महासागरों में जैव विविधता की रक्षा या कमजोर पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए कोई व्यापक संधि मौजूद नहीं है।

समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) के बारे में:

- समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीएलओएस), जिसे समुद्री सम्मेलन का कानून भी कहा जाता है, 1982 में अपनाया गया एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो सभी समुद्री और समुद्री गतिविधियों के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित करता है।

इसने तीन नए संस्थान बनाए गए हैं

1. **समुद्र के कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण।**
2. **अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण।**
3. **महाद्वीपीय शेल्फ की सीमा पर आयोग।**